(xii) यह पाया गया कि आमतौर पर वस्तुएं नियमित रूप से वितरित की जाती हैं, पर कुछ मामलों में काफी अन्तर से अनियमित वितरण की सूचना मिली है।

(xiii) गेहूं (60%) और मिट्टी का तेल (67%) के मामले में उपभोक्ताओं ने वितरित की गई मात्रा को पर्याप्त माना है, जबकि चीनी (61%) और चावल (55%) के मामले में अनेक स्थानों पर वितरित की गई मात्रा अपर्याप्त बताई गई है। संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरित की जाने वाली वस्तुओं के मामले में गेहूं (69.08%), चावल (57%) और चीनी (57%) की किस्म आमतौर पर "औसत" सूचित की गई है।

(xiv) अधिकांश प्रत्यर्थियों ने वस्तुओं अर्थात गेहूं (80.40%), चावल (77.21%), चीनी (89%) और मिट्टी का तेल (92.13%) के लिए व्यय करने में सक्षमता प्रकट की।

(xv) कुछ राज्यों में, लाभभोगियों ने उन वस्तुओं के संबंध में अपनी स्थानीय आवश्यकताएं और पसंद सूचित कीं जिन्हें वे संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरित किया जाना पसंद करेंगे। उदाहरणार्थ राजस्थान और गुजरात में मकई, ज्वार और बाजरा आदि को शामिल किए जाने की स्थानीय मांग है, केरल में गेहूं के मुकाबले चावल की मांग अधिक है। पश्चिम बंगाल में वितरण हेतु स्थानीय किस्म के चावल को पसंद किया जाता है। अध्ययन से पता चलता है कि वस्तुओं की पसंद के बारे में स्थानीय स्थिति (सामाजार्थिक और सांस्कृतिक) पर विचार करने की बहुत आवश्यकता है। वितरण के तहत वस्तुओं को शामिल करने और बदलने के लिए स्कीम में क्षेत्र विशिष्ट दृष्टिकोण को यथोचित महत्व देने की आवश्यकता है।

(xvi) "जानकार लोगों" के अनुसार संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्यान्वयन निम्न कारणों से असंतोषजनक है: खादयात्रों का अनियमित वितरण किया जाना, उच्च ढुलाई लागत होना और अपर्याप्त राजसहायता, वस्तुओं को नियमित रूप से और समय से न उठाना, आपूर्ति/वितरण में कम तोलना, भंडारण केंद्रों/सुपुर्दगी केंद्रों पर अच्छे किस्म की वस्तुओं को बदल देना, वितरण में गुणवत्ता और प्रक्रिया का पालन न करना और सतर्कता समितियों का अभाव होना।

Aims of Reforms in Trade Policy

44. DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR : Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether the reforms in Trade Policy were aimed at creating a free environment for trade, removing complexities through simplification and streamlining of procedures, increasing export production, sharpening India's competitive edge and focussing on quality and technological upgrading;

(b) if so, to what extent has this aim been achieved uptill now; and

(c) which are the areas in which we are lagging behind?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) Trade Policy reforms are a continuous process and various reform measures are taken in consultation with trade, industry and other concerned institutions. Trade has been made free, except for a negative list of imports and exports. These lists are also being continuously reviewed. Procedure have been simplified and further streamlined. Improvement in quality and technology upgradation are being given priority. Exporters are encouraged to upgrade the quality standards of their products. Consequent upon measures of reforms, exports have registered significant growth in recent years; exports during April-Sept., 1995 the latest period for which trade data are available in the current year, have recorded 26.4% growth, in US dollar terms. Emphasis is being laid on development of insfrastructure development and active involvement of State Governments.